

मुख्य समाचार :-

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को दी मंजूरी।
- राज्य मंत्रिपरिषद ने जनजातीय क्षेत्रों में सोलर पेनल लगाये जाने का लिया निर्णय।
- प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए गतिविधियां शुरू, भोपाल में कलेक्टर ने ली बैठक।
- प्रदेश में सर्दी की दस्तक के बीच कई जिलों में भारी बारिश जारी।

कैबिनेट-निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।

मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रबी 2025 के लिए लगभग 37 हजार नौ सौ 52 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है।

पीएम महाराष्ट्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मुंबई का दौरा करेंगे वे नेस्को एग्जिबिशन सेंटर, में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। 27 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आईएमडब्ल्यू 2025 का विषय "महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण" है। इसमें भारत के वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने के रणनीतिक रोडमैप को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें 85 से अधिक देश के एक लाख से अधिक प्रतिनिधि होंगे।

मंत्रिपरिषद निर्णय

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से सोलर पैनल लगाएं जाने का निर्णय लिया है। खेतों में बिजली के 132 केवी टावर के लिए 75 फीसदी राहत देते थे, जिसको बढ़ाकर अब सरकार की तरफ से 200 फीसदी कर दिया गया है।

पीएम आवास परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए वन टाइम पेमेंट करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। इसके लिए 80 करोड़ रुपये की राशि हर जिले को दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने ज्यादा किराया देकर सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों को शासकीय मकानों में रहने की अनुमति दी है।

कैबिनेट मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले कहा कि प्रदेश के स्थापना दिवस पर राजधानी और जिलों में विशेष कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल में एक नवंबर को 2 वर्ष में निवेश संवर्धन सहित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश से अर्जित उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाएगी। डिजिटल सेवाओं, मध्यप्रदेश ई-सेवा और इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल का लोकार्पण भी होगा। समृद्ध मध्यप्रदेश@ 2047 दृष्टि पत्र का विमोचन भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा।

निर्वाचन आयोग प्रदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 की घोषणा कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आज भोपाल में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें गहन पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि 2029 बीएलओ

और 205 सुपरवाइजर सर्वे काम को पूरा करेंगे 2003 की वोटर सूची में जिनका नाम नहीं है उनको 12 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाना होगा।

जीएसटी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, और इससे पूरे देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। बैतूल के मुकेश खंडेलवाल, ट्रेक्टर विक्रेता ने जीएसटी पर दी गई छूट को लेकर अपने विचार साझा किये हैं...

मुख्यमंत्री कर्मचारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार की सफलता कर्मचारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। प्रदेश के विकास में अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य कर्मचारी संघ द्वारा भोपाल में आयोजित दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न कर्मचारी संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे, पदनाम परिवर्तन के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मिलित कर नया आयोग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस का निराकरण कराया है। उन्होंने कहा कि नई भर्ती आरंभ कर 2 लाख नए पद भी सृजित किए जाएंगे। यूपीएससी की तर्ज पर एक परीक्षा कराई जाएगी, जिससे अलग-अलग पदों को भरने के लिए कई परीक्षाएं न कराना पड़े।

मौसम

प्रदेश के मौसम में एक और सर्दी की दस्तक है वहीं लगातार बारिश भी हो रही है। कल शाम तक झाबुआ और श्योपुर जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। थांदला और मेघनगर में 4 दशमलव 7 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं महूगंज, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, बड़वानी और धार में भी भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए नीमच, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट सहित 13 जिलों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच में प्रदेश में सबसे कम तापमान शिवपुरी में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

समाचार संक्षेप में :-

- शिवपुरी जिले में आगामी देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
 - अशोकनगर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
 - डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में 02 नवम्बर तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025" आयोजित किया जा रहा है।
 - जनजातीय लोककला एवं बोली विकास अकादमी एवं शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्वशासी कन्या महाविद्यालय, भोपाल द्वारा जनजातीय संग्रहालय में आयोजित दो दिवसीय परिसंवाद का समापन आज हुआ।
 - तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0" के अंतर्गत आज आगरमालवा और गुना में जागरूकता कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
-

